# बजट 2026-27 की मुख्य बातें

❖ दिल्ली सरकार का बजट 2026–27 – 1,03,700 करोड़ रुपये

- योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत बजट – 62,550 करोड़ रुपये
- स्थापना बजट – 41,150 करोड़ रुपये
- राजस्व बजट – 72,900.28 करोड़ रुपये
- पूंजीगत बजट – 30,799.72 करोड़ रुपये

❖ 2026–27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है, जो की 2025–26 के ₹1,00,000 करोड़ के बजट अनुमान से 3,700 करोड़ रुपये अधिक है। यह 3.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

❖ वर्ष 2026–27 के दौरान 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट को निम्नलिखित घटकों से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है:

राजस्व प्राप्ति :

- **स्वयं के कर राजस्व से ₹** 74,000 करोड़
    - जीएसटी – 43,500 करोड़ रुपये
    - वैट – 8,500 करोड़ रुपये
    - स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क – 11,000 करोड़ रुपये
    - राज्य आबकारी शुल्क – 7,200 करोड़ रुपये
    - वाहनों पर कर – 3,800 करोड़ रुपये
- स्वयं के गैर–कर राजस्व से 900 करोड़ रुपये
- केंद्र प्रायोजित योजना से 3931.16 करोड़ रुपये
- गृह मंत्रालय से सामान्य केंद्रीय सहायता और अन्य अनुदान के रूप में 968.01 करोड़ रुपये
- केंद्रीय सड़क निधि से 591 करोड़ रुपये
- स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत भारत सरकार से 1,500 करोड़ रुपये की निधि
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से 100 करोड़ रुपये की धनराशि
- दिल्ली विधानसभा के लिए नेवा परियोजना हेतु 1.90 करोड़ रुपये

पूंजीगत प्राप्ति

- आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए गए 16,700 करोड़ रुपये
- SASCI योजना के तहत भारत सरकार से लिया गया 2500 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 380 करोड़ रुपये की निधि – चंद्रावल जल निकासी परियोजना
- ऋण और अग्रिमों की वसूली: 487.93 करोड़ रुपये

प्रारंभिक शेष

- प्रारंभिक शेष से 1640 करोड़ रुपये

❖ कुल बजट 1,03,700 करोड़ रुपये है जिसमें शामिल है :

(राशि करोड़ में)

| क्षेत्र का नाम | 2026-27 | |
|---|---|---|
| | **BE** | **% Share** |
| शिक्षा | 19,326 | 18.64 |
| चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य | 13,034 | 12.57 |
| परिवहन, सड़कें एवं पुल | 12,613 | 12.16 |
| आवास एवं शहरी विकास | 11,572 | 11.16 |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | 10,537 | 10.16 |
| जल आपूर्ति एवं स्वच्छता | 9,000 | 8.68 |
| सार्वजनिक ऋण | 4,254 | 4.10 |
| ऊर्जा | 3,938 | 3.80 |
| ब्याज भुगतान | 2,734 | 2.64 |
| कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1,777 | 1.71 |
| अन्य | 14,915 | 14.38 |
| कुल योग | **1,03,700** | **100.00** |

❖ पहली बार है दिल्ली अपने विकास की यात्रा में *'Green Budget'* प्रस्तुत कर रही है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति, और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है इसलिए पूरे बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया है।

# सरकार के दस मुख्य संकल्प

## 1. INFRASTRUCTURE मजबूत बुनियाद - तेज़ विकास

i) विकसित दिल्ली- हरित दिल्ली के निर्माण के लिए MCD के लिए ₹11,266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके साथ ही बजट में NDMC और DCB के लिए कुल ₹146 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है।

ii) दिल्ली के Infrastructure के समग्र विकास के लिए, जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में PWD विभाग के लिए ₹5,921 करोड़ रुपये एवं शहरी विकास और आवास विभाग के लिए ₹7,887 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

iii) वर्ष 2026-27 में यमुनापार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए Trans Yamuna Development Board को ₹300 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है।

iv) अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, drainage, लाइट आदि के विकास के लिए ₹800 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।

v) दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को ₹787 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है।

vi) PWD की 1400 km सड़कों में से 400 km सड़कों का पुनर्विकास वर्ष 2025-26 में किया गया। वर्ष 2026-27 में 750 km सड़कों के end-to-end recarpeting एवं पुनर्विकास हेतु ₹1392 करोड़ का प्रस्ताव है।

vii) MCD की सड़कों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग ₹1,000 करोड़ प्रस्तावित हैं। Notified तथा non-conforming इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों और drainage systems का निर्माण हेतु ₹160 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

viii) बारापुल्ला Corridor, के कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट में 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, 25 करोड़ रुपये की लागत से नए foot-over bridges का भी कार्य शुरू किया जायेगा।

ix) **कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर** के विस्तार और **सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर** की परियोजना को मंजूरी दे दी गयी है। इसकी लागत ₹371 करोड़ है। इस काम के लिए ₹150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण हेतु ₹99.37 करोड़ की कुल लागत वाली परियोजना को भी स्वीकृति दी जा रही है।

x) ₹453.95 करोड़ की लागत से नजफगढ़ नाले के 54 km लम्बे भाग पर दोनों तरफ सड़क का निर्माण किया जाएगा।

xi) माननीय विधायकों को उनके विधान सभा छेत्र में स्थानीय विकास हेतु MLA-LAD योजना के लिए बजट में ₹350 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

xii) दिल्ली में नई आधुनिक फल, सब्ज़ी एवं फूल मंडी विकास हेतु टिकरी खानपुर और गाजीपुर में मंडियों का विकास किया जाएगा जो किसानों और व्यापारियों के सपनों के नए द्वार साबित होंगे।

xiii) सचिवालय, विभिन्न सरकारी भवनों, इत्यादि के रखरखाव के लिए ₹90 करोड़ रुपये के लिए एक centralised fund का प्रस्ताव किया किया गया है।

xiv) PWD के माध्यम से Yamuna periphery पर Cycle Track विकसित किया जाएगा, जिससे green mobility को बढ़ावा मिलेगा। Drainage system में innovation लाते हुए, drains पर solar panels स्थापित करने की योजना है, जिससे drains में कचरा डलने में कमी आएगी और Energy Generation भी संभव होगा। MCD के सहयोग से 5 नई modern parking facilities प्रस्तावित है, जिससे urban mobility को बेहतर बनाया जा सके।

xv) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में High और Low Tension Lines को underground करने हेतु **₹200 करोड़** के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है। यह दिल्ली की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और दुर्घटनाओं से सुरक्षा भी देगा।

xvi) **"प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना"** और **"सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना"** द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे कर दिल्ली को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाएगा

xvii) वर्ष 2026-27 में Fire Department के बजट को ₹530 करोड़ से बढ़ा कर ₹674 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत नए फायर सर्विस स्टेशन, 26 QRVs, आधुनिक मशीनरी और अत्याधुनिक उपकरण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

## 2. <u>WATER & SANITATION: स्वच्छ जल - स्वस्थ जीवन</u>

i) जल और Sewerage Infrastructure को सुदृढ़ करने के लिए, सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली जल बोर्ड के लिए ₹9,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

ii) दिल्ली के जल-संतुलन को सुदृढ़ करने के लिए 12.7 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन और 172 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन का विस्तार, जल आपूर्ति में 10 MGD की वृद्धि, और आगे 36 MGD अतिरिक्त जल का लक्ष्य है। Non-revenue जल को 45% से घटाकर 15% करना और हर घर नल से जल की दिशा में बढ़ना सरकार की दूरदृष्टि है।

iii) चंद्रावल Water Treatment Plant और पाइपलाइन के विस्तार के कार्य के लिए इस बजट में ₹475 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिससे लगभग 9 विधान सभाओं को लाभ मिलेगा।

iv) प्रस्तावित वज़ीराबाद Water Treatment Plant जल वितरण सुधार परियोजना कार्य उत्तरी दिल्ली की 10 विधान सभा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा। इस परियोजना के लिए मुख्य रूप से एशियाई विकास बैंक (ADB) से वित्तपोषण प्रस्तावित है।

v) सरकार ने Sewerage System को सुदृढ़ करते हुए STP क्षमता को 707 MGD से बढ़ाकर 814 MGD कर दिया है और लक्ष्य STPs की कुल क्षमता को बढ़ाकर 1500 MGD तक ले जाना है।

vi) नए Drainage Master plan की सिफारिशों के अनुसार PWD और संबंधित एजेंसियों द्वारा काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। हाल ही में सरकार ने पांच विधानसभा क्षेत्रों में जलभराव से राहत प्रदान हेतु ₹387 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से **MB Road पर ड्रेन** निर्माण **कार्य** को मंजूरी दी है और 2026-27 में इस कार्य के लिए ₹50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

vii) नए नालों का निर्माण और पुराने नालों का पुनरोद्धार "पुरातन में नवाचार" का उदाहरण है। इस वर्ष तैमूर नगर, कैलाश नगर, किराड़ी, बवाना जैसे क्षेत्रों में नालों का पुनर्विकास किया जायेगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए ₹610 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

## 3. HEALTH CARE सुलभ स्वास्थ्य - सुरक्षित जीवन

i) सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए ₹12,645 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए रुपये का प्रावधान रखा गया है।

ii) अधूरे अस्पतालों को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

- मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में ₹515 करोड़ के निवेश से अस्पताल परियोजनाएँ पूर्ण होंगी,
- Rao Tula Ram Memorial Hospital, Baba Saheb Ambedkar Hospital और Lal Bahadur Shastri Hospital में SASCI योजना के तहत infrastructure सुदृढ़ होगा।
- अधूरे पड़े हुए लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का भी निर्माण कार्य भी पूरा किया जायेगा।
- ICU अस्पतालों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए भी ₹150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- अस्पतालों में machineries, medical equipments और दवाइयों की ख़रीद के लिए ₹787 करोड़ आवंटित किए हैं। ये ख़रीद Central Procurement Agency (CPA) के माध्यम से होगी।

iii) जन आरोग्य योजना (PM-JAY) को सरकार ने दिल्ली में पहली बार लागू किया। ASHA वर्कर्स, आंगनवाड़ी कर्मी, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को शामिल कर इसका दायरा 7.5 लाख लाभार्थियों तक expand कर दिया गया है। अब इसमें transgenders को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए लिए ₹202 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

iv) PM-ABHIM के तहत 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Primary Health Care Centre) शुरू किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में नए 750 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए ₹1500 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

v) वित्त वर्ष 2026-27 में 11 integrated public health laboratories और 9 Critical Care Blocks बनाने का भी प्रावधान किया है। केंद्र की सहायता से श्री गुरु तेग़ बहादुर हॉस्पिटल में ₹200 करोड़ की लागत से trauma centre का निर्माण प्रस्तावित है।

vi) दिल्ली में medical colleges में UG की सीटों को 595 से बढ़ाकर 820 किया जायेगा। इसी प्रकार PG की seats को 553 से बढ़ाकर 762 किया जायेगा।

vii) सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में छात्र-छात्राओं के लिए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक-एक नए छात्रावास का निर्माण शुरू करेगी। इसके लिए ₹50 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।

viii) दिल्ली के नवजातों के लिए ***Advanced Newborn Monitoring and Optimal Lifecare:* 'अनमोल' योजना** के लिए ₹25 करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत नवजात बालको की एक रक्त की बूँद से 56 प्रकार के test दिल्ली सरकार द्वारा नि:शुल्क किये जाएँगे।

ix) स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक responsive और efficient बनाने के लिए, एक Real-Time Ventilator Bed Vacancy Monitoring System शुरू की जाएगी जिसमें private और सरकारी दोनों hospitals शामिल होंगे।

## 4. EDUCATION ज्ञान, कौशल और भविष्य निर्माण

i) शिक्षा के लिए ₹19,148 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। नए विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए ₹200 करोड़ और विद्यालयों के विस्तार के लिए ₹275 करोड़ आवंटित किया जा रहा है।

ii) **दिल्ली के सभी** सरकारी स्कूलों में Medical Rooms स्थापित करने का प्रस्ताव हमने इस बजट में किया है।

iii) दिल्ली सरकार कक्षा **9वीं में पढ़ने वाली लगभग 1 लाख 30 हज़ार छात्राओं को निःशुल्क cycle देगी**, जो उनका स्कूल पहुंचना आसान बनाएगा। इसके लिए ₹90 करोड़ का आवंटन किया गया है।

iv) सरकार द्वारा **10th pass meritorious students को laptops प्रदान किए जाएंगे**, जिसके लिए ₹10 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है।

v) वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 7000 कक्षाओं में Smart Board लगाये गए हैं वर्ष । 2026-27 में **8,777 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने का लक्ष्य हैं** और आने वाले समय में 21,000 स्मार्ट कक्षाओं तक विस्तार किया जाएगा। इसके लिए ₹150 करोड़ का का आवंटन किया गया है।

vi) Sports Hostel, खेल मैदानों व स्विमिंग पूलों के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किया गया है।

vii) Artificial Intelligence, Data Analysis, Exchange Programme, Exposure Visit के माध्यम से शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का संकल्प है। इन नई योजनाओं के लिए ₹18.5 करोड़ का आवंटन किया गया है।

viii) ₹720 करोड़ के तकनीकी शिक्षा बजट के साथ शाहदरा, पूसा और जेल रोड की तीन ITIs में Infrastructure का विस्तार किया जाएगा। GB Pant Engineering College और Polytechnic के नए भवन का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बजट में ₹100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव है।

ix) सरकार **ITI जहांगीरपुरी, ITI धीरपुर, ITI शाहदरा, ITI नरेला और ITI नंदनगरी के लिए Centre of Excellence** स्थापित कर रही है।

x) दिल्ली को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में नरेला में Educity बनाया जाएगा, अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा, और मुंडका में खेल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर भी बनाया जाएगा। National Law University के लिए भी ₹10 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है।

xi) दिल्ली सरकार "Talent Hunt Scheme" का आयोजन करने जा रही है। 70 विधानसभा क्षेत्रों के युवा प्रतियोगिताएं में भाग ले सकेंगे। इस योजना के लिए ₹10 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है।

xii) युवा अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व के गुणों से सशक्त बनें उस के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली में एक Sainik School की स्थापना करेगी ।

xiii) सरकार Private Play Schools Policy लेकर आ रही है। बच्चों के समग्र विकास के लिए Common Library Infrastructure और Digital Library System विकसित करेगी जिससे हर छात्र को knowledge resources तक समान access मिल सके।

xiv) दिल्ली सरकार Sports और health को ध्यान में रखते हुए, सरकारी stadiums में Rehabilitation Centres स्थापित करेगी

xv) सरकार Private Sports Academy Policy भी लेकर आएगी, जिससे सरकारी स्कूलों के छात्रों को बेहतर sports infrastructure और exposure मिलेगा, और private sector को भी opportunities मिलेंगी।

## 5. <u>Social Empowerment: समावेशी विकास - सबका सशक्तिकरण</u>

i) बजट में समाज कल्याण के लिए ₹2,392 करोड़ और SC/ST/OBC समाज के कल्याण हेतु ₹227 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है।

ii) अनुसूचित जाति बस्तियों के सुधार हेतु ₹80 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है।

iii) मामुरपुर, नरेला और उस्मानपुर में **mentally challenged लोगों के** आवास के लिए **₹35 करोड़** का प्रावधान किया गया है।

iv) सरकार द्वारा Senior citizens के लिए recreational activities का मंच प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए दिल्ली में ₹25 करोड़ के साथ **'वयो आनंद' योजना** की शुरुवात की जा रही है

v) JJ कॉलोनियों, अटल कैंटीन, बस्ती विकास और सामुदायिक ढांचे के लिए DUSIB के लिए ₹634 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है।

vi) वित्तीय वर्ष 2026-27 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए ₹7,406 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

vii) इसी के साथ-साथ ₹260 करोड़ के बजटीय प्रावधान के अंतर्गत, होली और दिवाली पर महिलाओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएँगे।

viii) ₹450 करोड़ के प्रावधान से महिलाओं और Transgenders के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा सुनिश्चित की जाएगी।

ix) **"दिल्ली लखपति बिटिया योजना"** सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जन्म से लेकर graduation तक, बेटियों के accounts में सरकार कुल 61 हज़ार रूपए डालेगी। Graduation होने तक बेटियों के खातों में maturity amount ₹1 लाख 20 हज़ार हो जाएगा। इसके लिए ₹128 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है।

x) महिला हाट outlets स्थापित कर महिलाओं के कौशल को बाजार से जोड़ने का सेतु बनाया जाएगा। इसके लिए ₹10 करोड़ का आवंटन किया गया है।

xi) प्रत्येक जिले में "मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र" स्थापित किए जाएंगे। आधुनिक infrastructure और community participation के साथ यह पहल दिल्ली के भविष्य को सुदृढ़ करेगी। इसके लिए ₹33 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है।

xii) सरकार कैमरों के संचालन और रखरखाव और अतिरिक्त 50,000 कैमरे लगाने के लिए ₹225 करोड़ आवंटित कर रही है।

xiii) PWD की सड़कों पर सभी पारंपरिक street lights को ऊर्जा-कुशल smart LED system से चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। इसके लिए ₹50 करोड़ का आवंटन किया गया है।

xiv) ₹16 करोड़ से 11 नए One Stop Centres बनाए जाएंगे जो संकट में हर महिला के लिए सहारा और सुरक्षा प्रदान करेंगे।

xv) **'DURGA' (Driving Upliftment and Rozgar for Women/ Transgender Green e-Auto) योजना** शुरू करने का प्रस्ताव है। जिसके पहले चरण में वर्ष 2026-27 में 1,000 महिलाओं और 100 transgenders को नया Auto permit प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।

xvi) वित्त वर्ष 2026-27 में 611 पालनों को सुदृढ़ करने के लिए **'समर्थ्य पालना'** के लिए ₹10 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव है।

xvii) दिल्ली सरकार बाल सुधार गृहों के बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए अलीपुर में integrated complex बना रही है, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ₹18 करोड़ का आवंटन किया गया है।

xviii) Child Care Centres के बच्चों की Aftercare एवं उनको मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ₹3.5 करोड़ का एक dedicated कोष बनाया जाएगा जिससे उनकी आजीविका, उच्च और तकनीकी शिक्षा, और कौशल विकास जैसी Aftercare जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

xix) सरकारी स्कूलों में new sanitary pad vending machines स्थापित की जाएंगी।

xx) Gig workers की protection और welfare को सुनिश्चित करने के लिए Gig Workers Welfare Board का गठन किया जाएगा। Transgender community के empowerment और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए Transgender Welfare Board स्थापित किया जाएगा। Auto और Taxi Drivers के लिए भी एक dedicated Auto-Taxi Drivers Welfare Board बनाया जाएगा, जो उनकी सुविधाओं और सुरक्षा पर केंद्रित होगा।

xxi) सरकार ₹62.6 करोड़ रुपये के आवंटन से veterinary hospitals का निर्माण और modernisation भी करेगी, जहाँ पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल के लिए आधुनिक उपकरण, सर्जरी और टीकाकरण की सुविधाएँ प्रदान की जाएगी ।

## 6. TRANSPORTATION सुगम सफर - स्मार्ट कनेक्टिविटी

i) वित्त वर्ष 2026-27 में परिवहन विभाग के लिए ₹8,374 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित है।

ii) दिल्ली को emission-free बनाने के लिए electric buses का fleet बढ़ाया जाएगा ।

- सरकार PM E-DRIVE के तहत चरणबद्ध तरीके से 6,130 अतिरिक्त E-buses introduce करने जा रही है।
- सरकार **मार्च 2027 तक दिल्ली में 7,500 बसें** शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है, **जिनमें 5,800 इलेक्ट्रिक बसें** शामिल हैं।
- लक्ष्य 2029 तक दिल्ली की सड़कों पर 12,000 EV buses दौड़ाने का है।

iii) DMRC की चरण IV और चरण V परियोजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ₹2,885 करोड़ प्रस्तावित है।

iv) सरकार ने दो और NaMo Bharat Corridor, दिल्ली-SNB और दिल्ली-पानीपत-सोनीपत NaMo Bharat Corridors, को भी मंजूरी दे दी है, जिससे NCR में Connectivity में सुधार होगा, प्रदूषण कम होगा, और fast transport facilities के कारण यात्रा समय में 60% तक की बचत होगी। RRTS के लिए ₹568 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

v) **Delhi Electric Vehicle Policy 2.0** के लिए ₹200 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

vi) वित्त वर्ष 2026-27 में बवाना, गाजीपुर, Savda घेवरा, GT Karnal Road और दिचाओं कलां, विभिन्न DTC Depots में पांच और ATS स्थापित किए जाएंगे, जिनकी लागत ₹50 करोड़ है।

vii) वित्त वर्ष 2026-27 में बस डिपो, charging infrastructure, और अन्य Capital Infrastructure के electrification के लिए ₹320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

viii) दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए flyover, elevated roads, और एक नई parallel Ring Road की परिकल्पना करते हुए feasibility study के लिए ₹10 करोड़ का आवंटन किया है।

## 7. <u>GOOD GOVERNANCE: पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन</u>

i) सरकार दिल्ली में Citizen-Centric Governance के लिए Decentralisation, Digitalisation और Transparency की दिशा में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। 13 जिलों में मिनी-सचिवालय बनाएँगे, जो प्रशासन को जनता के द्वार तक लाने का प्रयास है। इनके माध्यम से एक ही छत के नीचे integrated public services प्रदान की जा सकें। वित्त वर्ष 2026-27 में मिनी-सचिवालय के निर्माण कार्य के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव है।

ii) दिल्ली की प्रत्येक सम्पत्ति को Unique number (भू-आधार) देते हुए NGDRS Portal के माध्यम से सभी भूमि records को digitise किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता आएगी और property-related disputes एवं भ्रष्टाचार ख़त्म होगा।

iii) Policy Making को और ज़्यादा focused और Delhi-centric बनाने के लिए, **NITI Aayog की तर्ज पर "DITI" आयोग (Delhi Institutional Think Tank for Innovation)** का गठन किया जाएगा।

iv) जिला परियोजना निधि योजना के तहत DM को जिला स्तर पर विकास कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में ₹59 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

v) सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में sub-registrar स्तर पर पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए Passport Offices की तर्ज पर Modern, Paperless, और **Faceless Registration** प्रणाली शुरू करने जा रही है।

vi) DDMA के माध्यम से State-of-the-art Emergency Operation Centre स्थापित करने के लिए ₹10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

vii) सरकार ने दिल्ली में न्यायालयों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा, रोहिणी और राउज़ एवेन्यू में अतिरिक्त न्यायालय कक्ष एवं परिसर स्थापित करना तथा रोहिणी में एक family court की स्थापना करना शामिल है। इस उद्देश्य के लिए ₹230 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

viii) शेख सराय में क्षेत्रीय Forensic Science Laboratory के लिए एक नए भवन के निर्माण की नई परियोजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

ix) सरकार मौजूदा जेलों में भीड़ कम करने के लिए, भारत सरकार की मदद से, नरेला में High Security Jail का निर्माण शुरू करेगी।

x) भारत सरकार ने दिल्ली सरकार के **सार्वजनिक खाते (Public Account) को केंद्र के खाते से अलग करने की मंजूरी** दे दी है।

## 8. <u>INDUSTRY & STARTUP निवेश, नवाचार और रोजगार</u>

i) Small and Medium Enterprises की competitiveness और productivity बढ़ाने हेतु Common Facility Centres के निर्माण के लिए ₹48 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।

ii) सरकार एक **नई Warehousing Policy** लेकर आ रही है, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान आवंटित है। इस पहल से दिल्ली एक efficient और modern logistics hub के रूप में विकसित होगी, जिससे व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

iii) केंद्र सरकार के सहयोग से, दिल्ली में पहली बार RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) scheme लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, 32,000 MSMEs को training प्रदान की जाएगी, और 15,000 businesses को GeM और ONDC जैसे digital platforms से जोड़ा जाएगा,

iv) सरकार दिल्ली में एक सशक्त Semiconductor Manufacturing तथा Research & Development ecosystem स्थापित करने के लिए **Delhi Semiconductor Policy** लेकर आएगी, जो India Semiconductor Mission 2.0 के अनुरूप होगी।

v) सरकार **Delhi Drone Policy** भी लाने जा रही है, जिसके माध्यम से दिल्ली को advanced technology, research और high-tech manufacturing के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

## 9. <u>TOURISM & CULTURE विरासत और आधुनिकता का संगम</u>

i) पर्यटन विभाग का बजट पिछले वर्ष के ₹121 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹412 करोड़ किया गया है। Art, Culture और Language के लिए इस वर्ष ₹173 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

ii) **“Branding Delhi”** योजना के तहत, पर्यटन master plan, tourism policy और digital content development को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

iii) दिल्ली में पहली बार **International Film Festival** का आयोजन किया जा रहा है, ताकि दिल्ली global cultural map पर और मजबूती से स्थापित हो सके।

iv) पर्यटक दिल्ली से clean, vibrant और welcoming city experience लेकर जाए। इस दिशा में

- आने वाले वर्षों में लगभग 1,000 modern toilet blocks बनाए जाएंगे
- शहर के roundabouts, चौक-चौराहों का beautification किया जाएगा
- और 13 प्रमुख entry points पर grand welcome gates स्थापित किए जाएंगे

इन सभी infrastructure projects के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

v) इस वर्ष “दिल्ली सदन” के निर्माण का प्रस्ताव है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

vi) Delhi Institute of Hotel Management and Catering Technology का redevelopment करेंगे, ताकि hospitality sector में skilled manpower तैयार हो सके।

vii) दिल्ली सरकार एक नई Delhi Film Policy लेकर आ रही है, जिसके लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह policy creativity, employment और cultural expression को नई दिशा देगी।

viii) केंद्र सरकार के सहयोग से Town Hall को एक Global Heritage Centre के रूप में विकसित किया जाएगा।

ix) सरकार Animation, Visual Effects, Gaming और Comics (AVGC) industry के emerging ecosystem को मजबूत करने के लिए, **AVGC Policy** लेकर आ रही है ।

## 10. <u>GREEN BUDGET हरित विकास - स्वच्छ पर्यावरण</u>

i) कुल Budgetary Allocation का 21.44%, यानी ₹22,236 करोड़, इस वर्ष के Green Budget का हिस्सा है।

ii) पर्यावरण एवं वन क्षेत्र के लिए कुल बजट प्रावधान को पिछले वर्ष के ₹505 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष ₹822 करोड़ किया गया है।

iii) Green Budget यह सुनिश्चित करता है कि हर policy, हर decision, people और planet दोनों के हित में हो। इसके लिए

- सरकार ₹300 करोड़ की “Pollution Control & Emergency Measures” योजना (mechanical sweepers, anti-smog guns, water sprinklers) लेकर आ रही है
- MCD को ₹204 करोड़ pollution control के लिए आवंटित किये हैं
- Monitoring system के लिए ₹2 करोड़ (ICCC, war-room, mobile app, real-time tracking)
- सरकार World Bank collaboration के जरिए advanced technical solutions और monitoring systems लाने की दिशा में भी कार्यरत है।

iv) सरकार Urban forests, parks और green spaces के माध्यम से Delhi को फिर से Green Delhi बनाने के लिए committed हैं।

v) सरकार waste processing capacity को 7,000 metric tonnes से बढ़ाकर 15,000 metric tonnes per day तक बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं। और इसके लिए Narela, Okhla, Ghazipur और Tehkhand में Waste-to-Energy plant के विस्तार के लिए प्रावधान किये गए हैं।

vi) दिल्ली में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 1500 tonnes cow dung waste को भी process करके energy generation में बदला जाएगा। इससे emissions कम होंगे, fuel import घटेगा, और दिल्ली एक circular economy model के रूप में उभरेगी।

vii) दिल्ली सरकार **Carbon Credit Monetisation Scheme** को आगे बढ़ा रही है।

- यह scheme emission reduction को economic value में convert करेगी,
- एक मजबूत MRV system (Measurement, Reporting, Verification) के माध्यम से।
- इससे innovation बढ़ेगा और Delhi में sustainability और तेजी से आगे बढ़ेगी।

******************************************